भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3142

16 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

परियोजना की योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन

3142. श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में देश की आबादी का चालीस प्रतिशत के रहने और सकल घरेलू उत्पाद में पचहत्तर प्रतिशत का योगदान करने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अधिकांश शहरों में शहरी नगर नियोजन का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या परियोजना की योजना को प्रभावीरूप से बनाने और कार्यान्वयन के लिए सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमान (2011-2036) पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च, 2030 को भारत की अनुमानित शहरी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 37.25 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के अनुसार ऐसा अनुमान है कि 2030 में कुल जीडीपी में 75 प्रतिशत की शहरी हिस्सेदारी होगी।

(ग) और (घ) शहरी नियोजन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सितंबर, 2021 में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति)आयोग द्वारा लाई गई 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52 % संविधिक कस्बों और 76 % जनगणना नगरों में उनसे संबंधित स्थानिक विकास और अवसंरचनात्मक निवेश का मार्गदर्शन करने वाली कोई मुख्य योजना नही है।

(ड.) और (च) शहरी विकास राज्य का विषय होने के कारण, परियोजना का नियोजन और कार्यान्वयन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

*****